 ISSN-2583-2581

भारत की विदेश नीति: मोदी सरकार के शासनकाल के संदर्भ में (2014-19)

***रामचंद्र पालीवाल**

सारांश

स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतीय विदेश नीति में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत हुए। 1990 का दशक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का दशक रहा जिसने भारतीय विदेश नीति को गहरे रूप में प्रभावित किया। इसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के द्वि-ध्रुवीय से एक-ध्रुवीय में परिवर्तन के साथ हुई। इन परिवर्तनों के फलस्वरुप भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विदेश नीति के केंद्र को फिर से संगठित और पुनर्भाषित करना पड़ा। मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान भी भारतीय विदेश नीति में निरंतरता कायम रही और भारत ने अमेरिका, रूस, चीन और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सके। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारत की विदेश नीति के अंतर्निहित चालकों की खोज करना है और इसके प्रदर्शन के निर्णयों को रेखांकित करने वाली कुछ मान्यताओं का परीक्षण करना है जिसमें मुख्य मान्यता यह है कि मोदी स्वयं एक परिवर्तनकारी नेता हैं जो घरेलू और विदेश नीति के दोनों क्षेत्रों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। यह शोध-पत्र मोदी शासनकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। यह शोध-पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

कुंजी शब्द: विदेश नीति, मोदी सरकार, वैश्विक शक्तियां, विदेशमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

विदेश नीति: अर्थ एवं परिभाषा

किसी भी देश की विदेश नीति प्रमुखतया कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों पर आधारित होती है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों का संचालन करता है। इसी विदेश नीति के माध्यम से एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों का निरूपण करता है। वस्तुतः सभी देशों की विदेश नीति उनके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है और विदेश नीति में राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है। प्रो. मॉडलस्की के शब्दों में, "विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदलने तथा अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है"। विदेश नीति के संदर्भ में फेलिक्स ग्रास कहते हैं कि "कई बार किसी राष्ट्र के साथ संबंध न होना या उसके बारे में कोई निश्चित नीति न होना भी विदेश नीति के अंतर्गत आता है"। इस प्रकार किसी राष्ट्र की विदेश नीति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। यह सकारात्मक तब होती है, जब वह दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलने का प्रयास करती है तथा नकारात्मक तब कही जाती है, जब वह दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करती है। इस प्रकार किसी देश की विदेश नीति सामान्यतः उन सिद्धांतों का समुच्चय होती है जो उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है।

भारतीय विदेश नीति: एक परिचय

भारत की विदेश नीति भी अनेक सिद्धांतों और उद्देश्यों पर आधारित है जो इसकी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सहायक है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंगभेद नीति के खिलाफ खड़ा होना, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना, गुटनिरपेक्ष और गैर-प्रतिबद्ध रहना है और तीसरी दुनिया की एकता और एकजुटता बनाए रखना है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, विश्व

शांति की उपलब्धि, निरस्त्रीकरण, अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों की एकता शामिल है। इन उद्देश्यों को कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे पंचशील, नाम, सार्क और अन्य के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।

मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान भारत की विदेश नीति (2014-19):-

मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारत की सरकार द्वारा अन्य राज्यों के प्रति की गई नीतिगत पहलों से जुड़ी है। मोदी सरकार ने इन 10 सालों में विदेश नीति पर स्पष्ट छाप छोड़ी है और भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर काफी कवायद की है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं। साल 2023 के अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की थीं।

इस शासन के दौरान विदेश मंत्रालय का प्रभार सुब्रह्मण्यम जयशंकर को भारत की विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए दिया गया है। मोदी की विदेश नीति दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के विस्तारित पड़ोस और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को बेहतर करना शामिल है। इस संदर्भ में मोदी सरकार ने पहले 100 दिनों के अंदर भूटान, नेपाल और जापान की आधिकारिक यात्राएँ की हैं इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी आदि देशों की यात्राएँ शामिल है।

पृष्ठभूमि:

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पूर्व भूमिका में, मोदी ने प्रमुख एशियाई आर्थिक शक्तियों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई विदेशी यात्राएँ कीं। इसमें 2007 और 2012 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे के साथ बैठकें शामिल थीं, जिससे कथित तौर पर व्यक्तिगत संबंध बने। उन्होंने चीन और इज़राइल के साथ निवेश सौदों के लिए भी संपर्क किया जो रक्षा और कृषि से परे आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इज़राइली राजदूत एलन उशपिज़ के अनुसार मोदी को वाइब्रेंट गुजरात, एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने के उनके प्रयास के लिए व्यापक रूप से सराहा गया

जिसने उनके गृह राज्य गुजरात में निवेश का स्वागत किया और एक विकास समर्थक और व्यापार अनुकूल छवि बनाने में मदद की।

2014 के आम चुनावों के दौरान मोदी ने आम चुनाव प्रचार के दौरान कोई प्रमुख विदेश नीति भाषण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भारत के साथ सीमा पर चीन की संभावित आक्रामकता की बात कही। उन्होंने बांग्लादेश से अवैध आव्रजन पर भी ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में अपने चुनावी प्रचार के दौरान जोर देकर कहा कि देश के बाहर के हिंदू भारत में शरण लेने में सक्षम होंगे; यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे थे और उनके पूर्ववर्तियों से विश्व दृष्टिकोण में बदलाव की उम्मीद करना स्वाभाविक होगा। उन्होंने एक "मजबूत" विदेश नीति रखने का भी संकल्प लिया, जिसमें चीन के साथ व्यापार करना शामिल है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को अन्य भू-राजनीतिक पहलों की तुलना में व्यापार सौदों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।

मोदी की विदेश नीति का पहला नज़रिया 2013 में उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए दौड़ के दौरान सामने आया था, जब वे नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया नामक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो एक संवाद मंच था जिसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया:-

- अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करना उनकी प्राथमिकता होगी क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति और सौहार्द उनके विकास एजेंडे को साकार करने के लिए आवश्यक है।
- उन्होंने भारत में पैरा-डिप्लोमेसी की अवधारणा शुरू करने का संकल्प लिया, जहां प्रत्येक राज्य और शहर को अपने हित के देशों, संघीय राज्यों या शहरों के साथ विशेष संबंध बनाने की स्वतंत्रता होगी।
- कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियों को छोड़कर, जिनके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है, अधिकांश देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर हावी रहेगा।

मोदी ने औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले, भारत के पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। सभी सार्क देशों के नेताओं ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, साथ ही मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने भी इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया। इन

अतिथियों की सूची में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे आदि शामिल थे। चूंकि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना विदेश यात्रा पर थी इसलिए बांग्लादेश की संसदीय अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी उनकी जगह भारत आयी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगेय भी इस शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए।

मोदी सरकार ने पिछले दस वर्षों में भारतीय विदेश नीति को ऐसा नवीन रूप दिया जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजनीति में एक दिन भी काफी लंबा समय हो सकता है, लेकिन विदेश नीति में एक दशक को भी अक्सर गंभीर मूल्यांकन के लिहाज से पर्याप्त नहीं माना जाता हालांकि, पिछला दशक इस मामले में अपवाद रहा है। इस दौरान वैश्विक राजनीति में आए बदलावों की प्रकृति तो खास है ही, इनका दायरा भी व्यापक रहा है ऐसे में भारतीय विदेश नीति में भी बुनियादी बदलाव आना स्वाभाविक है। लेकिन विदेश नीति में आए इन बदलावों पर वैश्विक हालात और समीकरणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत भागीदारी की भी अमिट छाप नजर आती है।

नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्हें एक ऐसा क्षत्रप बताया जा रहा था जिसे विदेशी नीति का कोई अनुभव नहीं था। हिंदू राष्ट्रवादी नेता की उनकी छवि को भी खास तौर पर इस्लामी राष्ट्रों के साथ अच्छे रिश्तों की राह में बाधा माना जा रहा था लेकिन मोदी 'इंडिया फर्स्ट' के मंत्र को केंद्र में रखते हुए एक व्यावहारिक विदेश नीति को अपनाकर विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंकाने में कामयाब रहे। इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो।

पीएम मोदी की अगुवाई में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि वैश्विक मंच पर न केवल अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रोल में आने की नई दिल्ली की आकांक्षा लगातार मजबूत होती गई। वैश्विक मंच पर मोदी की कूटनीति ने भारतीय आकांक्षाओं को नए पंख दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले दशक तक वैश्विक मामलों में अहम भूमिका की पेशकश ठुकराने वाला देश एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील हो गया, जो ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान करने के लिए हमेशा आगे नजर आता है। पिछले दिनों सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे एक कमर्शियल जहाज को छुड़ाने का भारतीय नौसेना का अभियान इस बात का ताजा सबूत है।

मोदी के इस एक दशक के दौरान घरेलू और विदेशी का कृत्रिम विभाजन खत्म हो गया। भारत की मुख्य प्राथमिकता घरेलू मोर्चे पर विकास के जरिए हो रही कायापलट ही रही है। भारतीय कूटनीति भी विकास संबंधी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में संचालित होती रही। इसने बाहरी दुनिया से हमारे संपर्कों को एक खास व्यावहारिक नजरिया दिया जिसके तहत अब विचारधारा के बजाय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई। एक बेहतरीन उदाहरण तब सामने आया, जब यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पश्चिमी देशों के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखते हुए रूस से अपने विशिष्ट संबंध भी कायम रखने में कामयाब रहा।

इस दशक के दौरान जो सबसे बड़ा बदलाव इस मामले में देखने को मिला, वह है पाकिस्तान के साथ उलझे रहने के बजाय बंगाल की खाड़ी के समुद्री भूगोल पर बढ़ता जोर, जिससे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। इसे एक बड़ी उपलब्धि इस रूप में भी कही जा सकती है कि भारत के लिए पाकिस्तान के बजाय अपनी असली रणनीतिक चुनौती चीन पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया है।

गलवान घाटी में हुई भिड़ंत के बाद भारत ने यह स्टैंड लिया कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक दोनों देशों के रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते देखा जाए तो यह रुख बेहद कड़ा है, लेकिन पीछे हटने की कोई सूरत नहीं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सामरिक समीकरणों को आकार देने में भारत की बढ़ती दिलचस्पी नई वास्तविकता की ओर संकेत करती हैं। भारत अब अपने लिए बड़ी वैश्विक और क्षेत्रीय भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिए उसे पीछे हटना मंजूर नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत, विरोधियों को चुनौती देने और वैचारिक पृष्ठभूमि की चिंता किए बगैर दोस्तों को साथ लाने में सफल रहा है चाहे शी चिनफिंग के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का 2014 से विरोध करने की बात हो या उसकी सैन्य आक्रामकता का। उसी की शैली में जवाब देने की चाहे किसी औपचारिक गठबंधन में गए बगैर ही अमेरिका से करीबी स्थापित करने की बात हो या यूरोपीय देशों के सहयोग से अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने की भारत ने इस दौरान गजब की व्यावहारिकता दिखाई है।

अतीत में सिद्धांत को लेकर उलझे रहने वाला भारत आज विश्व मंच पर एक जिम्मेदार स्टेकहोल्डर के तौर पर मौजूद है। कोरोना महामारी के दौरान उसकी वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए दुनिया इस नई भूमिका में उसके आत्मविश्वास की झलक देख चुकी है। भारत अब

वैश्विक समस्याएं हल करने में दिलचस्पी ले रहा है। नेतृत्वहीनता के दौर से गुजर रही दुनिया में मोदी के नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इसका ताजा उदाहरण है भारत की G-20 देशों की अध्यक्षता हासिल करना है।

मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नई दिल्ली में एनडीए सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस समय यह माना जा रहा था कि विदेश नीति मोदी की शासन व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी होगी, क्योंकि उन्हें विदेशी देशों के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था।

हालांकि, इन दस वर्षों में विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। भारत और पूरी दुनिया ने ऐसी प्रकृति की चुनौतियों का अनुभव किया है जो वैश्विक समुदाय ने कई दशकों में नहीं देखी थी। इनमें से सबसे दुर्बल करने वाली कोविड-19 महामारी थी जो 100 वर्षों के अंतराल के बाद घटित होने वाली एक डरावनी और भयावह घटना थी। इससे पहले कि दुनिया महामारी से निपट पाती, उसे दो अप्रत्याशित संघर्षों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास टकराव ने घेर लिया। इस अवधि के दौरान कुछ अन्य घटनाक्रमों में जापान और ताइवान के खिलाफ पूर्वी चीन सागर में चीन का बढ़ता आक्रामक व्यवहार शामिल था। दक्षिण चीन सागर में कई आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ) देशों के खिलाफ और भारत और भूटान के खिलाफ अनिर्धारित और विवादित भूमि सीमा पर चीन द्वारा आक्रामकता दिखाना शामिल है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन तथा अन्य अनेक चुनौतियों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वर्तमान विदेश मंत्री एस. जयशंकर की सहायता से, तथा अपने साहसिक, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व के बल पर, विश्व में पसंदीदा साझेदार, तर्क की आवाज और सर्वसम्मति निर्माता के रूप में भारत की छवि और पहचान को बढ़ाया है।

मोदी की विदेश नीति के विभिन्न पहलू:-

नेबरहुड फर्स्ट की नीति:

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पहली पहलों में से एक 'पड़ोसी पहले' नीति थी, जब उन्होंने 26 मई, 2014 को अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन) और मॉरीशस के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। उन्होंने 31 मई, 2019 को अपने दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक

सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), किर्गिस्तान और मॉरीशस के नेताओं को आमंत्रित किया था। पड़ोसी पहले नीति की सफलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत के अपने पड़ोसियों (पाकिस्तान, चीन और हाल ही में मालदीव को छोड़कर) के साथ संबंध आज 2014 की तुलना में बहुत मजबूत और गहरे हैं।

अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री मोदी की नेपाल की पहली यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री की नेपाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। तब से, प्रधानमंत्री मोदी ने चार बार नेपाल की यात्रा की है। नवंबर 2014 में सार्क शिखर सम्मेलन के लिए; 2018 में दो बार, एक बार द्विपक्षीय यात्रा पर और फिर बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए; और 2022 में नेपाली प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर लुम्बिनी की यात्रा पर चौथी बार। सितंबर 2014 में दोनों देशों के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक 23 साल के अंतराल के बाद हुई थी।

इसी प्रकार, बांग्लादेश के साथ लंबे समय से लंबित भूमि सीमा समझौते (1975 में हस्ताक्षरित इंदिरा-मुजीब समझौता) के सर्वसम्मति से अनुसमर्थन से यह मजबूत संदेश गया कि भारत अपने महत्वपूर्ण पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का इच्छुक है।

श्रीलंका के साथ भी, मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 2022 में अस्तित्व के संकट और ज़रूरत के समय में श्रीलंका को भारत द्वारा निर्णायक और जोरदार राजनीतिक और आर्थिक समर्थन, उसकी तत्काल और आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 4.50 बिलियन डॉलर प्रदान करके, द्विपक्षीय साझेदारी में विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

पाकिस्तान, चीन और मालदीव के साथ संबंधों में आई गिरावट भारत की किसी विफलता या गलत कदम के कारण नहीं है, बल्कि इन देशों द्वारा घरेलू राजनीतिक या रणनीतिक कारणों से उठाए गए कदमों के कारण है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवादी हमलों के साथ-साथ चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का भी कड़ा जवाब दिया है। मुइज्ज़ू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार हाल ही में 'इंडिया आउट' अभियान के दम पर सत्ता में आई है, लेकिन भारत द्वारा स्थिति को परिपक्व और राजनेता की तरह संभालने से संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

पश्चिम एशिया के प्रति नीति:

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों का गहरा और व्यापक होना है। पहले ये देश भारत को पाकिस्तान द्वारा बनाए गए इस्लाम के धार्मिक चश्मे से देखते थे। आज ऐसा नहीं है। भारत इन देशों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र और फिलिस्तीन सहित इनमें से कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है।

यूएई ने पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ओआईसी (इस्लामिक देशों के संगठन) के विदेश मंत्रियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा, पश्चिम एशियाई देशों में से किसी ने भी भारत द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने के खिलाफ कोई रुख नहीं अपनाया। इसके विपरीत, यूएई ने आतिथ्य और पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जम्मू और कश्मीर में 5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत अपने आठ सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों को, जिन्हें जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, कतर के अमीर द्वारा माफ कर दिया गया और उन्हें भारत लौटने के लिए रिहा कर दिया गया।

पूर्व की ओर देखो की नीति:

भारत की एक्ट ईस्ट नीति आसियान देशों के साथ-साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, प्रशांत द्वीप राष्ट्रों और अन्य के साथ आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक, संपर्क और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को विस्तारित और विविधतापूर्ण बनाने में उल्लेखनीय रूप से सफल रही है।

भारत-अमेरिका संबंधों में बदलाव:

पिछले 10 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और भरोसे में उल्लेखनीय वृद्धि और मजबूती देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के साथ काम किया है और इन सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। यह राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंध के रूप में उभरा है। दोनों देश महत्वपूर्ण और

उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हरित हाइड्रोजन, रक्षा, सेमीकंडक्टर चिप्स और कई अन्य सहित 60 संवाद मंचों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जून 2023 में राष्ट्रपति बिडेन द्वारा राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने और दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का भी सम्मान दिया गया (पहली बार उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को 2016 में ओबामा के कार्यकाल के दौरान संबोधित किया था)। प्रधानमंत्री मोदी नवंबर 2017 में क्वाड के पुनरुद्धार और पिछले तीन वर्षों में इसे शिखर स्तर तक उन्नत करने में भी सक्रिय भागीदार रहे हैं।

रूस-यूक्रेन संघर्ष में नजरिया:

भारत ने पश्चिम से भारी दबाव के बावजूद, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना न करके अपनी सामरिक स्वायत्तता का दृढ़तापूर्वक प्रदर्शन किया है, बल्कि अपने लोगों को सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात भी जारी रखा है।

जी-20 की अध्यक्षता:

संभवतः जी-20 की अध्यक्षता का सफल संचालन, तार्किक और सारगर्भित, पिछले दशक में विदेश नीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का शिखर माना जा सकता है। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि भारत एक सर्वसम्मत नेता घोषणापत्र तैयार करने में सफल होगा, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देशों के यूक्रेन में संघर्ष पर व्यापक रूप से भिन्न रुख थे, और दूसरी तरफ रूस और चीन के। लेकिन भारत पहले ही दिन अकल्पनीय को प्राप्त करने में सक्षम था। इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सम्मान और पारस्परिक लाभ के व्यक्तिगत संबंधों को दिया जा सकता है, जिसे वे अधिकांश विश्व नेताओं के साथ विकसित करने में सक्षम रहे हैं। भारत के लिए G20 की सफल अध्यक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई। भारत ने अफ्रीकी संघ को समूह के 21वें सदस्य के रूप में शामिल करवाया और G20 की अपनी अध्यक्षता की उल्लेखनीय सफलता के परिणामस्वरूप वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और विश्वामित्र (विश्व का मित्र) के रूप में उभरा।

सांस्कृतिक पुनर्संतुलन:

राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों में दूरगामी पहलों के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए योग, आयुर्वेद,

बाजरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि जैसे कई सांस्कृतिक विषयों को बढ़ावा दिया है। इसने 'वसुधैव कुटुम्बकम', वैश्विक परिवार की एकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्राचीन विचार नेता के रूप में भारत की स्थिति को सक्रिय रूप से पेश करने की कोशिश की है।

निष्कर्ष:

वैश्विक राजनीति के इस चुनौतीपूर्ण दौर में मोदी ने भारत को एक अनोखी और विशेष आवाज दी है। आज किसी भी अन्य बड़ी शक्ति के मुकाबले भारतीय अपने भविष्य को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी नजरिया रखते हैं और यही चीज उनके विदेशी संबंधों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। मोदी का नेतृत्व उस भावना को न केवल समझ रहा है बल्कि उसका प्रभावी इस्तेमाल भी कर रहा है। मोदी की खासियत है कि वह इस राष्ट्रीय आकांक्षा को अपनी विदेश नीति में गूंथने के साथ-साथ अपनी छवि से भी जोड़ने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने पिछले 10 वर्षों में उत्पन्न हुई व्यापक चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को अत्यधिक विश्वसनीय रूप से तैयार किया है। आज दुनिया संक्रमण के दौर से गुज़र रही है। वैश्विक उथल-पुथल और अशांति भारत के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी प्रस्तुत करती है, ताकि वह वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति को बेहतर बना सके और आने वाले वर्षों में एक अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विश्व मंच पर उभर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. हर्ष वी. पंत. (2024). मोदी सरकार में कैसी बदली भारत की विदेश नीति. 02 अप्रेल, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन.
2. हर्ष वी. पंत. (2023). मोदी सरकार ने पूरे किये अपने 08 साल: स्वतंत्र और व्यवहारिक विदेश नीति पर फोकस. 10 अगस्त, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन.
3. शैलेंद्र कुमार. (2023). मोदी शासन के 9 साल में कितनी बदल गई विदेश नीति? इसकी उपलब्धियां और चुनौतियां. 26 मई, नई दुनिया.
4. इयान हॉल एंड सुमित गांगुली. (2022). इंट्रोडक्शन: नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 59(1), पेज 1-8.

5. राजेश मिश्रा. (2022). भारतीय विदेश नीति: भूमंडलीकरण के दौर में. दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रा. लि.
6. राजीव सीकरी. (2017). भारत की विदेश नीति: चुनौती और रणनीति. दिल्ली: सेज भाषा.
7. वी. एन. खन्ना. (2016). भारत की विदेश नीति. दिल्ली: विकास पब्लिशिंग.
8. सुमित गांगुली. (2015). दुनिया से जुड़ाव: 1947 से भारत की विदेश नीति. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. सुमित गांगुली. (2015). भारतीय विदेश नीति. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. अशोक सज्जनहार. (2014). प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के दस वर्ष: बड़ी चुनौतियों और बड़ी उपलब्धियों का युग. 06 मार्च, फर्स्ट पोस्ट.
11. अंकित पांडा. (2014). भारत की यूपीए सरकार और विदेश नीति. द डिप्लोमैट पत्रिका.
12. कांति पी. बाजपेयी और हर्ष वी. पंत. (2013, संपादित). भारत की विदेश नीति: एक अध्ययन. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
13. आर. एस. यादव. (2013). भारत की विदेश नीति. दिल्ली: पीयरसन.
14. बिमल प्रसाद. (2012). द मैकिंग ऑफ़ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. दिल्ली: विस्टा पब्लिशिंग.
15. जे. एन. दीक्षित. (2012). भारतीय विदेश नीति. दिल्ली: प्रभात पेपरबैक्स.
16. यू. आर. घई. (2011). भारतीय विदेश नीति. जालंधर: न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी.
17. वी. पी. दत्त. (2010). स्वतंत्र भारत की विदेश नीति. दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट.
18. बी. एम. जैन. (2008). ग्लोबल पॉवर: इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1947-2006. नागपुर: लेक्सिंगटन बुक्स.
19. हर्ष वी. पंत. (2006). भारतीय विदेश नीति और चीन. स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, अक्टूबर, इश्यू-04.